तीसरे विश्व के देशों से व्यापार

1826. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकटाड सम्मेलन के बाद तीसरे विश्व के किन देशों के साथ भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या भारत अविकसित देशों से अधिक से अधिक व्यापार करने की दिशा में पहल कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इससंबन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मई 1976 में हुए अंकटाड सम्मेलन के बाद विभिन्न देशों के साथ भारत के व्यापार के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग). जी हां । विकासशील देशों समेत विभिन्न देशों को भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं । इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) कतिपय देशों के साथ व्यापार करार तथा व्यापार प्लान सम्पन्न करना ।

(ii) बाजार सर्वेक्षण, व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना, प्रचार, प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि जैसे निर्यात संवर्द्धन कार्यकलापों में सहायता देना ।

(iii) विदेश स्थित हमारे वाणिज्यक कार्यालयों को सुदृढ़ बनाना ।

(iv) नौवहन सुविधाओं में सुधार करना ।

(v) विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखायें खोलना ।

(vi) क्रेता तथा अन्य प्रतिनिधि मंडलों को भारत आमंत्रित करना ।

(vii) निर्यातकों को विभिन्न सुविधायें देना ।

Misuse of Import Licences in Gujarat

1827. SHRI ARVIND M. PATEL:
SHRI VEKARIA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any investigation has been made in respect of misusing of import licences in Gujarat State during the last three years;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the action taken by Government against the defaulters?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) Yes, Sir; in 53 cases.

(b) (i) Misuse of imported raw materials.

(ii) Evasion of information to the Industries Commissioner, Ahmedabad with regard to utilisation of imported raw material.

(iii) Closure of manufacturing activities.

(c) Defaulters have been punished under the Imports (Control) Order, 1955, by way of debarment from import assistance for specified periods. Their names have been published in the Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences. 3 cases have been handed over to CBI.